सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

प्रेरणा

"जो लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं, वे पहले ही नीचे होते हैं।"

साप्ताहिक मौसम

दिन	अधिकतम	न्यूनतम
शुक्रवार	21°	7°
शनिवार	21°	9°
रविवार	19°	11°
सोमवार	20°	10°
मंगलवार	20°	10°
बुधवार	20°	9°
वीरवार	20°	10°

*आंकड़े आईएमडी के अनुसार

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-7 • 06 FEBRUARY TO 12 FEBRUARY 2026 • VOLUME 29 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY
CONFUSED ABOUT CAREER!
Unsure of what to do after 10th/12th/Graduation?
Whether to Study in India or Abroad?
What should I do after 10th-Science, Commerce or Arts?
Should I consider Computer or Mechanical Engineering?
What is better for me - MBA in Marketing or MBA in Finance?
Should I pursue Chartered Accountancy or Law after 12th?
Do I have the aptitude for Architecture and Designing?
Get Career Guidance from our Expert Career Counseling Team Free of Cost
E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact :9317776662, 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University. Phagwara.
*T&C apply

रवनीत बिट्टू को 'गद्दार' कहने पर भड़के पीएम मोदी, कहा-

राहुल गांधी की 'सिख विरोधी' मानसिकता हुई उजागर

नई दिल्ली. बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा भाजपा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को संसद के बाहर 'गद्दार' कहे जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर 'सिख-विरोधी मानसिकता' का आरोप लगाया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देते हुए मोदी ने राज्यसभा में कहा कि कल कांग्रेस के राजकुमार ने एक सांसद को 'गद्दार' कहा। उनका अहंकार नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। कई लोग कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं। कांग्रेस कई बार विभाजित हुई है, कई नेता अन्य पार्टियों में चले गए हैं। तब उन्होंने उन्हें गद्दार नहीं कहा। लेकिन उन्होंने बिट्टू को गद्दार कहा क्योंकि वह सिख थे।

मोदी ने कहा कि यह सभी सिखों का अपमान था। यह सिख समुदाय के प्रति कांग्रेस की गहरी नफरत की अभिव्यक्ति थी। वे इस सदन में इस घटना के लिए माफी मांग सकते थे, लेकिन सिखों के प्रति अपनी नफरत के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह एक सांसद थे जिनके परिवार ने देश के लिए बलिदान दिए। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने राजनीतिक विचार बदल दिए, वे 'गद्दार' बन गए? प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कल क्या हुआ? कांग्रेस के युवराज, जिनका दिमाग़ शातिर है, ने सदन के एक सांसद को 'गद्दार' कह दिया। उनका अहंकार चरम पर है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने वाले किसी और को गद्दार नहीं कहा। लेकिन उन्होंने उस सांसद को गद्दार कहा, सिर्फ़ इसलिए कि वह सिख हैं। यह सिखों का अपमान है, गुरुओं का अपमान है। यह कांग्रेस में सिखों के प्रति भरी नफ़रत की अभिव्यक्ति है।

अपने एक घंटे 35 मिनट के भाषण में विपक्ष के नेता पर और हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बिट्टू का जिक्र किया कि वह परिवार के उन सदस्यों में से एक थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और पूछा, "सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा बदल ली, क्या वह गद्दार बन गए?" उन्होंने आगे कहा कि यह कोई छोटी बात नहीं है। देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि किसी नागरिक को गद्दार कहा जाए? यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोग कांग्रेस को डुबा देंगे। लोकसभा के स्थगित होने के एक दिन बाद, जब विपक्ष के हंगामे के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से ठीक पहले सदन स्थगित कर दिया गया था, तब उन्होंने कांग्रेस पर लगातार हमले किए। कई उदाहरणों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, जिसमें जेएनयू में हाल ही में लगाए गए मोदी विरोधी नारे भी शामिल थे। हालांकि, विपक्ष ने भाषण शुरू होते ही नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन किया, और प्रधानमंत्री के राज्यसभा को संबोधित करते समय वे सदन से बाहर चले गए।

श्री गुरु रविदास महाराज जी के उपदेश अनुसार समानता वाले समाज की रचना के लिए पंजाब सरकार प्रतिबद्ध : मान

कहा- आज श्री खुरालगढ़ साहिब में होने वाले राज्य स्तरीय समागम में पंजाब की पूरी कैबिनेट संगत के साथ उपस्थित होगी

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार श्री गुरु रविदास महाराज जी द्वारा दिए गए उपदेशों पर चलते हुए समानता वाले समाज की रचना के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु जी की महान विरासत को बनाए रखने के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा 6 फरवरी को होशियापुर जिले में स्थित खुरालगढ़ में राज्य स्तरीय समागम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रकाश पर्व के अवसर पर पूरी कैबिनेट संगत के साथ श्री गुरु रविदास जी को श्रद्धा और सम्मान अर्पित करने के लिए नतमस्तक होगी।

भगवंत सिंह मान ने समस्त संगत से इस राज्य स्तरीय समागम में पूरे धार्मिक उत्साह और बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मान सरकार ने श्री गुरु रविदास जी महाराज के 649वें प्रकाश पर्व को पूरे धार्मिक उत्साह के साथ मनाने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं, साथ ही 2027 में ऐतिहासिक 650वें प्रकाश पर्व के लिए साल भर चलने वाली राज्य स्तरीय तैयारियाँ शुरू की हैं। श्री खुरालगढ़ साहिब में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय समागम का आयोजन किया गया है जिसमें संतों, आध्यात्मिक नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों, डिप्टी स्पीकर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की बड़ी संख्या में भागीदारी होगी तथा 6 फरवरी को श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के उपरांत समापन होगा। भगवंत मान सरकार ने संगत की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएँ और निर्विघ्न प्रबंध सुनिश्चित किए हैं।

भारत की पहली सहकारिता-आधारित टैक्सी सेवा का शुभारंभ

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। यह एक सहकारी स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म है जो ड्राइवरों को मालिक की तरह काम करने की सुविधा देता है, जिससे कमीशन शून्य हो जाता है और कीमतों में अचानक होने वाली बढ़ोतरी (सर्ज प्राइसिंग) समाप्त हो जाती है। इस सेवा का उद्देश्य उबर और ओला जैसे ऐप्स को टक्कर देना है। सहकारिता मंत्रालय ने भारत टैक्सी को परिवहन क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल बताया है, जो ड्राइवरों (जिन्हें सारथी कहा जाता है) को स्वामित्व, संचालन और मूल्य सृजन के केंद्र में रखती है, जिससे वे शोषणकारी एग्रीगेटर-आधारित मॉडलों से मुक्त हो जाते हैं। अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी सेवा टैक्सी चालकों के लिए बड़ी सुविधा प्रदान करेगी और उन्होंने कहा कि टैक्सी क्षेत्र में औपचारिक रूप से सरकार नहीं, बल्कि सहकार प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली में प्रत्येक सारथी चालक टैक्सी का मालिक होगा और यह ढांचा एक क्रांतिकारी आर्थिक परिवर्तन लाएगा। गुजरात के अमूल की तरह, यह विश्व में अपनी तरह का एक अनूठा सहकारी मॉडल है। आपकी टैक्सी के पहिए सारथी समुदाय के लाभ के लिए चलेंगे - यही सहकारिता की भावना है। शाह ने आगे बताया कि भारत टैक्सी की परिकल्पना एक एकीकृत परिवहन मंच के रूप में की गई है जो दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी "सारथी दीदी" महिला यात्रियों और चालकों की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

गृह मंत्री ने कहा कि टैक्सी सेवा तीन वर्षों में शुरू हो जाएगी और सरकार प्लेटफॉर्म द्वारा अर्जित राजस्व का 20% हिस्सा लेगी, जबकि शेष राशि प्रत्येक सारथी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अब तक, किराया पहले कंपनी के खाते में जमा किया जाता था और कमीशन काटा जाता था। यह प्रणाली अब समाप्त होती है। ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए 1,200 से अधिक "सारथियों" (ड्राइवर पार्टनर्स) ने भाग लिया।

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए जालंधर में सांझ राहत केंद्र का उद्घाटन

चंडीगढ़/जालंधर (जालंधर ब्रीज). पीड़ित-केंद्रित पुलिसिंग और महिलाओं के लिए सहायता व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब पुलिस ने जालंधर के सिविल अस्पताल में घरेलू हिंसा की पीड़ितों के लिए एक समर्पित सहायता केंद्र 'सांझ राहत केंद्र' की स्थापना की है। केंद्र का उद्घाटन करते हुए कम्युनिटी अफेयर्स डिवीजन एवं महिला मामलों की स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (स्पेशल डीजीपी) गुरप्रीत कौर दिओ ने कहा कि यह केंद्र सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से परेशानियों का सामना कर रही महिलाओं को समय पर मानसिक-सामाजिक और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर स्पेशल डीजीपी के साथ पुलिस कमिश्नर (सीपी) जालंधर धनप्रीत कौर भी मौजूद थीं।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 33 घंटे बाद यातायात बहाल

मुंबई. मुंबई और पुणे को जोड़ने वाले मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बीते दो दिनों से जारी ट्रैफिक का संकट आखिरकार गुरुवार सुबह समाप्त हो गया। लगभग 33 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। इस महाजाम के कारण हजारों यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।

अधिकारियों के अनुसार, यह समस्या मंगलवार शाम को शुरू हुई थी। खंडाला घाट के दुर्गम और पहाड़ी इलाके में एक गैस टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया था। टैंकर में ज्वलनशील गैस होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल प्रभाव से दोनों तरफ का यातायात रोकना पड़ा। घाट सेक्शन की भौगोलिक स्थिति और गैस रिसाव के खतरे को देखते हुए टैंकर को हटाने और गैस को सुरक्षित तरीके से खाली करने में लंबा समय लगा। अब मुंबई की ओर जाने वाले मार्ग पर देर रात एक बजकर 46 मिनट पर यातायात फिर से शुरू हो सका। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे भारत का

पहला छह-लेन का प्रवेश नियंत्रित टोल एक्सप्रेसवे है। 94.5 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मुंबई, रायगढ़ और नवी मुंबई को पुणे से जोड़ता है। टैंकर मंगलवार शाम करीब पांच बजे मुंबई की ओर जाने वाले मार्ग पर पलट गया जिससे भारी यातायात जाम लग गया और व्यस्त एक्सप्रेसवे पर हजारों वाहन घंटों तक फंसे रहे। जाम इतना भीषण था कि वाहनों की करीब 20 किलोमीटर तक लंबी कतार लग गई। इस यातायात संकट के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित यात्रियों को भोजन, पानी और शौचालय की सुविधा नहीं मिल पाई।

चीमा द्वारा कनाडा के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल की मेज़बानी

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बीती शाम पंजाब भवन में कनाडा के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल की मेज़बानी की। नई दिल्ली स्थित कनाडा के उच्चायोग के औपचारिक अनुरोध पर आयोजित इस बैठक के दौरान पंजाब और अल्बर्टा प्रांतों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने तथा आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। कनाडाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अल्बर्टा सरकार की स्वदेशी संबंधों की मंत्री राजन साहनी ने किया। उनके साथ प्रीमियर कार्यालय के स्टेकहोल्डर्स एडमिनिस्ट्रेटर जतिंदर सिंह ततला, अल्बर्टा की यूनाइटेड कंजरवेटिव पार्टी के नेता के वरिष्ठ सलाहकार हैप्पी मान, स्वदेशी संबंध विभाग की कार्यवाहक

संचालन निदेशक जेनेवीव टरकोट, जग रूप कलों, जसविंदर ग्रेवाल तथा पुनीत कुमार गोयल भी शामिल थे। बैठक के दौरान 'इन्वेस्ट पंजाब' के अधिकारियों ने राज्य में उपलब्ध विभिन्न निवेश अवसरों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। वीडियो और पावरपॉइंट प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल को पंजाब के औद्योगिक ढांचे तथा राज्य सरकार द्वारा 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 172 स्टेशनों का काम पूरा

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के दीर्घकालिक पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत स्टेशनों के सुधार हेतु मास्टर प्लान तैयार करना और चरणबद्ध तरीके से उनका कार्यान्वयन करना शामिल है। मास्टर प्लान में स्टेशन और आवागमन क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों हिस्सों से जुड़ाव, स्टेशन भवन का सुधार, प्रतीक्षा कक्षों, शौचालयों, बैठने की व्यवस्था और पानी के बूथों में सुधार, यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े फुट ओवरब्रिज/एयर कॉनकोर्स का प्रावधान, लिफ्ट/एस्केलेटर/रैंप की व्यवस्था, प्लेटफार्म की सतह में सुधार/उपलब्धता और प्लेटफार्म के ऊपर आवरण का प्रावधान, 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क की व्यवस्था करना, पार्किंग क्षेत्र, मल्टीमॉडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध सुविधाएं, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकतानुसार एग्जीक्युटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्धारित स्थान, हरियाली आदि की व्यवस्था करना इत्यादि शामिल हैं। इस योजना में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल समाधान, आवश्यकतानुसार बैलास्टलेस ट्रैक का प्रावधान, चरणबद्ध कार्यान्वयन और व्यवहार्यता के साथ-साथ दीर्घकालिक रूप से स्टेशन पर शहर केंद्र का निर्माण जैसी परिकल्पनाएं भी शामिल हैं। अब तक इस योजना के तहत विकास के लिए 1337 स्टेशनों की पहचान की गई है। फिलहाल, 172 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है।

भारतीय रेलवे (आईआर) द्वारा देशभर के पुलों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, आईआर में रेलवे पुलों के निरीक्षण की एक सुस्थापित प्रणाली है। सभी पुलों का निरीक्षण वर्ष में दो बार नामित अधिकारियों द्वारा किया जाता है, एक बार मानसून शुरू होने से पहले और एक बार मानसून के बाद विस्तृत निरीक्षण। इसके अतिरिक्त, मुख्य पुल अभियंता (सीबीई) द्वारा निर्धारित स्थिति के आधार पर कुछ पुलों का निरीक्षण अधिक बार भी किया जाता है। महत्वपूर्ण और बड़े पुलों का व्यापक तकनीकी निरीक्षण इस प्रकार किया जाता है कि ऐसे 20 प्रतिशत पुलों का निरीक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है। पुलों की मरम्मत/मजबूतीकरण/पुनर्वास/पुनर्निर्माण एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है और यह पुलों के निरीक्षण के आधार पर की जाती है। 2022-2025 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान, भारतीय रेलवे में 8,626 रेलवे पुलों की मरम्मत/पुनर्वास/मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण किया गया है। आईआरसीटीसी और रेलवे अधिकारी ट्रेनों में खानपान मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अचानक और नियमित निरीक्षण करते हैं। आईआरसीटीसी ने ट्रेन में दी जाने वाली सेवाओं की निरंतर निगरानी और यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए पर्यवेक्षकों और खानपान सहायकों को तैनात किया है। निरीक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए, आईआरसीटीसी ने मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाओं की अनुभागीय निगरानी के लिए अतिरिक्त हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर नियुक्त किए हैं।

वर्तमान में, रेल मंत्रालय के अधीन देश में तीन कोच निर्माण इकाइयां कार्यरत हैं। कोच निर्माण इकाइयों के विकास की लागत स्थान, निर्मित किए जाने वाले कोचों के प्रकार, नियोजित उत्पादन क्षमता और स्थापित की जाने वाली मशीनरी और संयंत्र जैसे कारकों पर निर्भर करती है। कोच निर्माण इकाइयों के विकास पर व्यय लंबी अवधि में और कई चरणों में होता है, जिसमें प्रारंभिक स्थापना के साथ-साथ समय-समय पर सुविधाओं का उन्नयन और विस्तार भी शामिल है। उदाहरण के लिए, रायबरेली स्थित नवीनतम कार्यरत कोच निर्माण इकाई - मॉडर्न कोच फैक्ट्री - की स्थापना पर 3,042.83 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त, तीन कार्यरत कोच निर्माण इकाइयों, अर्थात् इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला और मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रायबरेली के उन्नयन/विस्तार से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए 2443 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

बिलिंग और कैशलेस भुगतान के लिए प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों की स्थापना। बिलिंग को बढ़ावा देने और अधिक शुल्क वसूलने पर अंकुश लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाना। अधिक शुल्क वसूलने के मामलों में, यदि कोई हो, तो उचित दंड लगाया जाए। केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में पूछे गए प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता सूची प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा

राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों के साथ की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों-सह-डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक कर मतदाता सूचियों के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता मैपिंग गतिविधियों की समीक्षा करते हुए निर्वाचन जानकारी के योजनाबद्ध कवरेज, शुद्धता और समय पर अपडेट सुनिश्चित करने हेतु जिला-वार प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक के अवसर पर उन्होंने स्पष्ट रूप से पहचान में न आने वाली फोटो और गलत प्रविष्टियों से संबंधित मामलों के समाधान पर विशेष जोर देते हुए निर्वाचन फॉर्मों के संग्रह और निपटारे की स्थिति की भी समीक्षा की। इस दौरान जिला अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ऐसे मामलों का तुरंत निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही ईआरओ नेट पर आवेदनों की लंबित स्थिति (पेंडेंसी) पर भी विस्तृत चर्चा की गई और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूचियों की एकरूपता एवं शुद्धता बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी तथा आवेदनों के शीघ्र निपटारे की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ईसीआई नेट पर "बुक ए कॉल" सुविधा के बारे में जागरूकता फैलाने के महत्व पर भी जोर दिया, जिसके तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) पारदर्शी एवं समयबद्ध शिकायत निवारण के लिए मतदाताओं को कॉल-बैक सहायता प्रदान करते हैं।

राष्ट्रपति भवन को अंदर से देखना है! जानें कैसे होगी टिकट की बुकिंग और पूरी डिटेल

Travelling राष्ट्रपति भवन को बाहर से देखकर अंदर जाने का सपना देखते हैं। तो जान लें भवन के अंदर कौन लोग जा सकते हैं और जाने के लिए किन चीजों की होगी जरूरत। बुकिंग से लेकर टाइमिंग की पूरी डिटेल।

• **जालंधर ब्रीज** . फीचर

भारत के राष्ट्रपति का ऑफिशियल घर यानी राष्ट्रपति भवन दिल्ली की सबसे आइकॉनिक चीज है। जिसे बाहर से देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। जब आपको पता चले राष्ट्रपति भवन के अंदर के हॉल, डाइनिंग एरिया और आर्किटेक्चर को देखने का मौका मिल रहा तो कौन नहीं जाना चाहेगा। एच शेप में बना ये स्ट्रक्चर्ड मास्टरपीस 330 एकड़ की जमीन में फैला है। राष्ट्रपति भवन में पूरे 340 कमरे हैं। और, ये एक इमारत नहीं बल्कि भारत के इतिहास, डेमोक्रेसी और हेरिटेज की भव्यता को भी रिप्रेजेंट करता है।

अगर आप सोच रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन को अंदर से देखना आम पब्लिक के लिए सपने जैसा है तो गलत है। दरअसल, राष्ट्रपति भवन के कुछ हिस्सों को आम पब्लिक भी विजिटर के तौर पर देख सकते हैं।

राष्ट्रपति भवन के इन हिस्सों को देखने की है इजाजत

- राष्ट्रपति भवन के अंदर जाकर कुछ हिस्सों को पब्लिक के देखने के लिए खोला जाता है। जिसमे वो एरिया शामिल है जहां पर राष्ट्रपति दुनियाभर के लीडर से मिलते हैं। फार्मल डाइनिंग होती है।
- हॉल, जहां पर नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी होती है।
- भवन के कुछ हिस्से, जिसमे म्यूजियम भी शामिल है, वहां पर अब तक के सभी राष्ट्रपति के पोट्रेट लगे हैं। उन हिस्सों को भी देखने का मौका मिलता है।
- तो अगर आप भी राष्ट्रपति भवन को अंदर से देखने का प्लान बना रहे तो जान लें कैसे होगी टिकट की बुकिंग और क्या है टाइमिंग।
- राष्ट्रपति भवन देखने के लिए कैसे

बुक करें टिकट

- राष्ट्रपति भवन को अंदर से देखने के लिए पहले से बुकिंग जरूरी है। इसकी बुकिंग ऑफिशियल वेबसाइट से होती है। एक बार बुकिंग हो जाने के बाद एंट्री के लिए सिक्योरिटी चेक होते हैं और ग्रुप में गाइड अंदर लेकर जाते हैं।

टिकट का प्राइज और समय

- भवन देखने के लिए प्रति व्यक्त 50 रुपये कीमत होती है।
- विजिटर मंगलवार से लेकर रविवार तक राष्ट्रपति भवन विजिट कर सकते हैं।
- सुबह 9:30 से 4:30 बजे तक टाइमिंग है और लास्ट एंट्री 4 बजे तक ही होती है।
- विजिटर को राष्ट्रपति भवन देखने के लिए पूरे 45 मिनट का समय मिलता है।

कैसे पहुंचे

- राष्ट्रपति भवन पहुंचने के लिए सबसे पास का मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सेक्रेट्रिएट है। जहां गेट नंबर 38 एक किमी दूर है।
- वहीं पटेल चौक मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 38 से दो किमी दूर है।
- इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है
- राष्ट्रपति भवन देखने के लिए पहले से बुकिंग जरूरी है।
- अपने साथ वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जरूर ले जाएं।
- मोबाइल फोन, बैग, कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर ले जाना मना है।
- सर्किट 1- शुक्रवार, शनिवार और रविवार को खुले रहते हैं।
- सर्किट 2- सोमवार को छोड़कर बाकी छह दिन खुला रहता है।
- सर्किट 3- शुक्रवार से रविवार अगस्त से लेकर मार्च तक खुला रहता है।

LIFESTYLE

काम में उलझकर खुद को भूल गए हैं? वर्क-लाइफ बैलेंस के लिए सीखें ये 6 मंत्र

डेडलाइन्स, नोटिफिकेशन्स और जिम्मेदारियों के बीच वर्क-लाइफ बैलेंस बनाना मुश्किल हो गया है। लेकिन कुछ आसान रोजमर्रा की आदतें अपनाकर आप तनाव कम कर सकते हैं और जीवन में संतुलन ला सकते हैं।

• **जालंधर ब्रीज** . फीचर

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। लगातार काम का दबाव, स्क्रीन टाइम और मानसिक थकान हमें अंदर से खोखला कर देती है और असंतोष बढ़ने लगता है। ऐसे में कुछ छोटे लेकिन असरदार बदलाव आपकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। वर्क-लाइफ बैलेंस कोई एक दिन में मिलने वाला लक्ष्य नहीं, बल्कि रोज की छोटी आदतों से बनने वाली जीवनशैली है।

6 आदतें जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं:

इकिगाई (Ikigai) का कॉन्सेप्ट अपनाएं

जापान की अवधारणा 'इकिगाई' का मतलब है- वो काम जो आपको पसंद हो, जिसमें आप अच्छे हों और जिसकी दुनिया को भी जरूरत हो। जब आपका काम आपकी रुचि और स्किल्स से मेल खाता है, तो काम बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। रिसर्च बताती है कि इकिगाई खोज लेने वाले लोग कम तनाव में रहते हैं और ज्यादा संतुलित जीवन जीते हैं।

2. Pleasure, Peace और Purpose को प्राथमिकता दें

खुशी के तीन स्तंभ हैं- सुख, शांति और उद्देश्य। केवल सुख बिना शांति के अस्थिरता लाता है और उद्देश्य बिना शांति के बर्नआउट। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी एक्टिविटीज शामिल करें जो मन को आनंद, शांति और अर्थ दें।

3. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करें

दिन में सिर्फ 10 मिनट की माइंडफुल ब्रीदिंग या ध्यान आपकी सोच को साफ कर सकता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार, नियमित मेडिटेशन से एंग्जायटी और डिप्रेशन कम होता है, जिससे काम और निजी जीवन में स्पष्टता आती है।

4. स्पष्ट सीमाएं (Boundaries) तय करें

ऑफिस टाइम और पर्सनल टाइम को अलग रखें। काम के बाद ईमेल या कॉल से दूरी बनाएं और सहकर्मियों को अपनी उपलब्धता स्पष्ट करें। इससे रिश्तों, शौक और सेल्फ-केयर के लिए समय मिलता है।

5. कृतज्ञता (Gratitude) की आदत डालें

हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। हार्वर्ड हेल्थ की स्टडी के अनुसार, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से खुशी बढ़ती है और तनाव घटता है, जिससे काम और जिंदगी का टकराव कम महसूस होता है।

6. लोगों से जुड़ाव बनाए रखें

दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों से जुड़ना मानसिक मजबूती देता है। मेंटर्स, सपोर्ट ग्रुप्स या कम्युनिटी इवेंट्स से जुड़कर आप अकेलापन कम कर सकते हैं और संतुलन बनाए रखने के नए नजरिए पा सकते हैं।

डिस्क्लेमर : इस लेख के सुझाव सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन सुझावों और जानकारी को किसी प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर न लें। किसी भी स्थिति में एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

पनीर से बनाएं मजेदार गट्टे, नये तरह की सब्जी देख सब हो जाएंगे खुश

पनीर को फ्राई करके या फिर कच्चा ही शाही, पालक, कड़ाही या फिर मटर के साथ तो कई बार बनाई और खाई होगी। लेकिन इस बार वहीं बोरिंग पनीर बनाने की बजाय ट्राई करें पनीर से बने गट्टे की सब्जी। इसका स्वाद सबको भाएगा...

• **जालंधर ब्रीज.** रेसिपी

कड़ाही पनीर, शाही पनीर, मटर पनीर जैसे कई तरह से पनीर की सब्जी बनाकर खाई होगी। लेकिन इन सारी सब्जियों से बोर हो चुकी हैं तो अब बनाएं पनीर गट्टे की सब्जी। जिसका यूनिक प्रेजेंटेशन और टेस्ट दोनों ही सबको पसंद आएगा। तो बस झटपट नोट कर लें पनीर गट्टा बनाने की बिल्कुल आसान सी रेसिपी।

पनीर गट्टा सब्जी बनाने की सामग्री

- 200 ग्राम पनीर
- एक कप बेसन
- धनिया पाउडर
- लाल मिर्च पाउडर
- जीरा पाउडर
- नमक स्वादानुसार
- 2 प्याज
- आधा कप दही
- अदरक-मिर्ची का पेस्ट
- गरम मसाला
- हींग
- दो टमाटर का पेस्ट

पनीर गट्टा की सब्जी बनाने की सामग्री

- सबसे पहले पनीर से गट्टे तैयार कर लेंगे।
- पनीर गट्टा बनाने के लिए किसी बाउल में बेसन लेंगे। उसमे हींग, नमक स्वादानुसार, हल्दी थोड़ी सी डाल दें। साथ ही लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और अजवाइन के कुछ दाने डालकर मिक्स करें और पानी डालकर इसे आटे की तरह नर्म गूंथ लें।
- अब पनीर को घिस कर बहुत थोड़ी सी मात्रा में चाट मसाला और नमक मिक्स करें। बेसन के साथ मिक्स होकर ज्यादा ना हो जाए।
- अब बेसन की लोई बनाएं और उसमे पनीर के छोटे बॉल्स बनाकर उसमे भरें।
- पानी को गर्म करें और उसमे इन बेसन में भरे पनीर बॉल्स को डालकर पकाएं।
- जब ये पक जाएं तो इन्हें साइड में रख लें।
- अब ग्रेवी बनाने के लिए कड़ाही में तेल गर्म करें।
- उसमे जीरा, दालचीनी और तेजपत्ता डालें। साथ ही बारीक कटे प्याज को डालकर भूनें।
- प्याज जब हल्के ट्रांसपैरेंट हो जाएं तभी अदरक और मिर्च के पेस्ट को बनाकर डाल दें।
- अच्छी तरह से भुनने के बाद इसमे टमाटर का पेस्ट डालें।
- जितनी देर में टमाटर भुन रहे हैं दही में कुछ मसाले मिक्स करके साइड रख लें।
- दही लेकर उसमे हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर डालें।
- टमाटर भुन जाए तो गर्म मसाला डालें और आधा मिनट भूनें।
- फिर दही डालकर तेजी से चलाएं जिससे कि दही फट ना जाएं।
- अच्छी तरह से मसाले को भुनें और एक कप गुनगुना पानी डालकर पकाएं।
- सबसे आखिर में पनीर के बने गट्टों को डालकर ढंककर दो मिनट पकाएं।
- बस रेडी है मजेदार पनीर गट्टे की सब्जी।
- सर्व करते टाइम इन गट्टों को दो भाग में काट दें। जिससे इनका यूनिक कलर कॉम्बिनेशन सबको अट्रैक्ट कर सके।

बोर्ड परीक्षा के दौरान पेरेंट्स की ये बातें तोड़ देती हैं आत्मविश्वास, मनोचिकित्सक से जानें किन बातों का रखें ध्यान...

PARENTING

जालंधर ब्रीज (फीचर) . बोर्ड एग्जाम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए तनाव का समय बन जाता है। घर में किताबें खुली रहती हैं, माहौल गंभीर हो जाता है और बातचीत का केंद्र सिर्फ पढ़ाई और परीक्षा रह जाती है। इस दौरान माता-पिता बच्चों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन कई बार उनके शब्द अनजाने में बच्चों की एंग्जायटी बढ़ा देते हैं। मनोचिकित्सकों के अनुसार, परीक्षा के समय क्या कहा जा रहा है उतना ही नहीं, बल्कि कैसे कहा जा रहा है, यह भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है।

अक्सर माता-पिता यह कहते हैं, 'यह बोर्ड है, इससे ही सब तय होगा' या 'अब नहीं पढ़े तो आगे कुछ नहीं होगा।' ये बातें बच्चों को प्रेरित करने के इरादे से कही जाती हैं, लेकिन बच्चों के मन में यह डर बैठा देती हैं कि एक गलती उनका पूरा भविष्य खराब कर सकती है। इसका नतीजा यह होता है कि बच्चा पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय डर और घबराहट में आ जाता है।

इसी तरह तुलना करना भी बच्चों का आत्मविश्वास तोड़ देता है। 'देखो शर्मा जी का बेटा कितना पढ़ रहा है' या 'तुम्हारे दोस्त को तो सब आता है' जैसी बातें बच्चों की चिंता को और बढ़ा देती हैं। बच्चा खुद को दूसरों से कम समझने लगता है, जबकि पढ़ाई एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है।

हर समय पढ़ाई की याद दिलाना भी बच्चों को मानसिक रूप से थका देता है। बार-बार 'पढ़ लिया?', 'कितना हुआ?' जैसे सवाल बच्चों पर लगातार दबाव बनाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि उनकी मेहनत कभी पर्याप्त नहीं होगी, जिससे चिड़चिड़ापन और थकान बढ़ती है।

इसके उलट, जब माता-पिता कहते हैं, 'हम तुम्हारे साथ हैं', 'पूरी कोशिश करना ही काफी है' या 'नंबर मेहनत को दिखाते हैं, तुम्हारी काबिलियत को नहीं', तो बच्चों को राहत मिलती है। प्रयास पर बात करने से बच्चा खुलकर अपनी परेशानी साझा करता है और सीखने की प्रक्रिया से जुड़ा रहता है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि शांत माहौल, सामान्य दिनचर्या और भावनात्मक सहयोग बच्चों की एंग्जायटी को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। बोर्ड एग्जाम जरूरी हैं, लेकिन बच्चे उनसे ज्यादा जरूरी हैं। इस समय माता-पिता के शब्द बच्चों के लिए सहारा भी बन सकते हैं और बोझ भी। सही भाषा और धैर्य बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखता है।

डिस्क्लेमर : *इस लेख में दी गई सूचना पूरी तरह सोशल मीडिया रील पर आधारित है। जालंधर ब्रीज इसकी सत्यता और सटीकता की जिम्मेदारी नहीं लेता है।*

डाइट में फाइबर पूर्ति के लिए ढेर सारी सब्जी नहीं, इन फूड्स को चुनें, थोड़ी मात्रा में मिलेगा पर्याप्त फाइबर

Health भोजन में पर्याप्त मात्रा में फाइबर की कमी को पूरा करने के लिए ज्यादातर लोग सब्जियां और सलाद खाते हैं। लेकिन ढेर सारी सब्जियों और सलाद का पोर्शन खाकर पेट भरने की बजाय इन स्मार्ट...

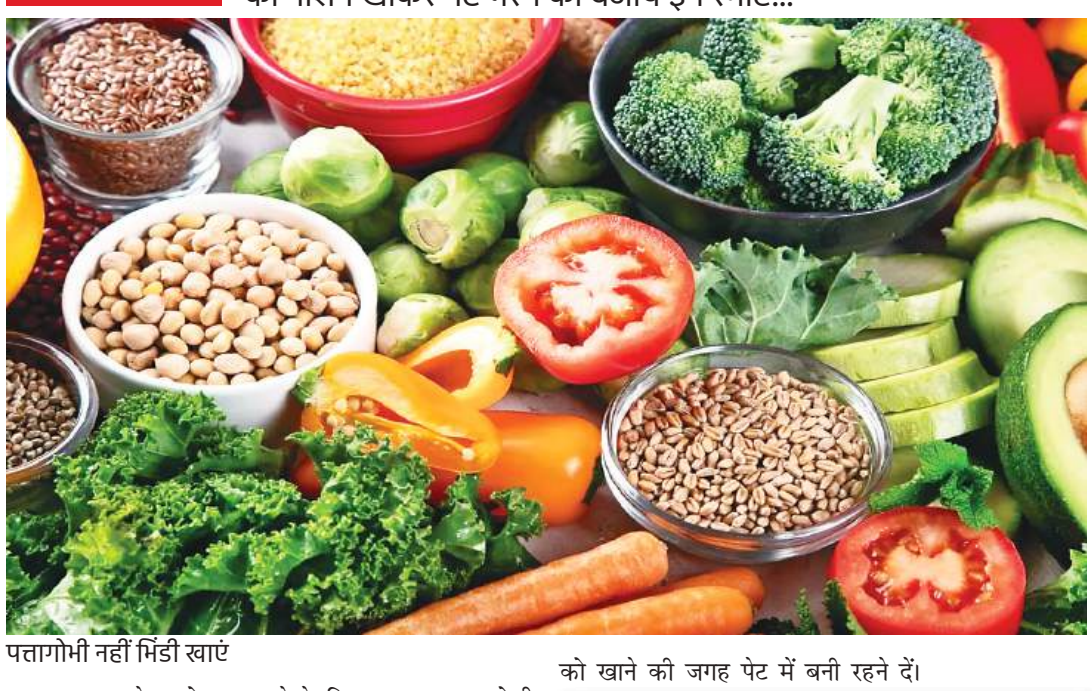

• **जालंधर ब्रीज.** हेल्थ केयर

खाने में फाइबर की मात्रा कम है और कब्ज से लगातार जूझ रहे हैं। और, हर दिन सलाद, सब्जियों को भर-भरकर खा रहे हैं। तो अपनी डाइट को थोड़ा स्मार्ट बनाएं। ऐसे फूड्स को चुनें, जिसकी कम मात्रा में ज्यादा फाइबर हो। जिससे ना केवल आपके पेट में दूसरे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए जगह हो बल्कि आप ओवर ईटिंग से खुद के वेट लॉस प्रोग्राम को बिगाड़ ना दें।

फाइबर इनटेक बढ़ाना है तो सब्जियों और सलाद के पोर्शन साइज को बढ़ाने की बजाय इन फूड्स को खाना शुरू करें। जानें टमाटर, खीरा के सलाद से लेकर सब्जियों की तुलना में इन फूड्स में कितना फाइबर मिलेगा।

केले और संतरे की बजाए खाएं अमरूद

अगर आप फाइबर के इनटेक के लिए केले और संतरे को खा रहे हैं। तो जान लें कि एक केला और दो संतरे से जहां केवल 3 ग्राम के करीब फाइबर मिलेगा। वहीं एक एवरेज साइज के अमरूद से आपको 7-8 ग्राम फाइबर मिल जाएगा।

टमाटर-खीरा का सलाद नहीं खाएं इसबगोल

फाइबर इनटेक के लिए आप प्लेट भरकर खीरा, प्याज, टमाटर का सलाद बनाकर खाते हैं। इसकी बजाय एक चम्मच इसबगोल की भूसी को लें। इसमे 5-6 ग्राम फाइबर है जो कब्ज को दूर भगाने में मदद करेगा।

दाल से ज्यादा फाइबर राजमा में मिलेगा

प्रोटीन के साथ फाइबर इनटेक पूरा करना है तो दाल के अलावा राजमा खाएं। एक कटोरी दाल में अगर 2-3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा तो वहीं राजमा एक कटोरी खाने से पूरे 6 ग्राम फाइबर की पूर्ति होगी।

पत्तागोभी नहीं भिंडी खाएं

फाइबर इनटेक को पूरा करने के लिए पूरा एक पत्तागोभी खाने की जरूरत नही है। इसकी बजाय केवल एक कटोरी भिंडी खाएं। ये आपके बॉडी को 6 ग्राम फाइबर देगी। तो अगली बार फाइबर की पूर्ति के लिए केवल सलाद सब्जी ढेर सारा ना खाकर इन फाइबर रिच फूड्स को कम मात्रा में खाएं और बाकी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए दूसरे फूड्स को खाने की जगह पेट में बनी रहने दें।

डिस्क्लेमर : *यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।*

सिर्फ समझौता नहीं, हमारे भविष्य का रोडमैप है भारत-यूरोपीय संघ एफटीए

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक कूटनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इससे लाखों रोजगार पैदा होंगे तथा भारतीय युवाओं और किसानों के लिए व्यापक अवसरों का सृजन होगा। इसके साथ ही लगभग 2 अरब की उस आबादी के लिए धन पैदा होगा जो मिल कर वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक-चौथाई भाग है।

विश्व की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच यह एफटीए इतिहास के सबसे बड़े व्यापार समझौतों में से एक है। वास्तव में यह व्यापार समझौते से ज्यादा व्यापक है। यह कृत्रिम मेधा (एआई), रक्षा और सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने वाली विस्तृत साझीदारी है। इस एफटीए से भारत के हर क्षेत्र और नागरिक तथा खास तौर से निर्धन तबकों को लाभ पहुंचेगा।

यह एफटीए नियम आधारित व्यापार और आर्थिक नीतियों में स्थिरता सुनिश्चित करता है जिससे भारत स्वदेशी और विदेशी निवेश के लिए और ज्यादा आकर्षक बनेगा। यह छोटे व्यवसायियों, स्टार्टअप संस्थाओं और कामगारों के लिए अनेक अवसर पैदा करेगा। विश्व ने प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा की सराहना करते हुए इस एफटीए को सभी समझौतों से बड़ा बताया है। यह वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में स्थिरता को मजबूत करता है। यह भारत और यूरोपीय संघ को मुक्त बाजार, पूर्वानुमान क्षमता और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध भरोसेमंद साझीदारों के रूप में स्थापित करता है।

भारत ने व्यापार मूल्य के हिसाब से यूरोपीय संघ में अपने 99 प्रतिशत से ज्यादा निर्यात के लिए अभूतपूर्व बाजार पहुंच प्राप्त की है जिससे 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को बल मिलेगा। इस एफटीए से कपड़ा, रेडीमेड वस्त्र, चमड़ा, फुटवियर, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरी सामान और ऑटोमोबाइल जैसे श्रमसाध्य क्षेत्रों को निर्णायक मजबूती मिलेगी।

इस समझौते से लगभग 33 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात पर 10 प्रतिशत तक टैरिफ खत्म होगा। इससे कामगारों, हस्तशिल्पियों, महिलाओं, युवाओं तथा सूक्ष्म, छोटे और मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) का सशक्तीकरण होगा। वैश्विक मूल्य श्रृंखला से भारतीय व्यवसाय ज्यादा गहराई से जुड़ेंगे और वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की भूमिका मजबूत होगी।

यह समझौता व्यवसायियों और पेशेवर तबके के लिए दूसरे देशों में जाने को आसान बनाते हुए शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी,

पीयूष गोयल
(लेखक भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं)

वित्तीय सेवाओं और कंप्यूटर जैसे सेवा क्षेत्रों में अवसरों के नए द्वार खोलता है। इन प्रतिबद्धताओं से उच्च मूल्य वाले रोजगार के अवसरों के खुलने के साथ ही प्रतिभा, नवोन्मेष और संवहनीय आर्थिक विकास के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होती है।

व्यापार समझौते गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने की मोदी सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। इस रणनीति में क्रांतिकारी सुधारों और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा सभी पक्षों के लिए लाभकारी समझौते के उद्देश्य से विकसित और पूरक अर्थव्यवस्थाओं के साथ बातचीत शामिल है। यह रणनीति भारत को अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करने और उन लाभकारी बाजारों तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाती है जो कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की रक्षा करते हुए श्रमसाध्य क्षेत्रों में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विकसित देशों के साथ व्यापार समझौते भारतीय उद्योगों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करते हैं और उपभोक्ताओं को विश्व स्तरीय उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। यूपीए सरकार ने बिना सोचे-समझे भारत के बाज़ार खोल दिए थे, इसके उलट मोदी सरकार ने ऐसे समझौते किए हैं जिनमें टैरिफ में कमी धीरे-धीरे की जाती है। जिससे उद्योगों को उचित नीतिगत समर्थन के साथ अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है।

प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण का केंद्र है। पिछले सप्ताह इसी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था: "आइए, इस साल हम अपने पूरे सामर्थ्य के साथ गुणवत्ता को प्राथमिकता दें। हमारा एकमात्र मंत्र गुणवत्ता, गुणवत्ता और केवल गुणवत्ता होना चाहिए। कल की तुलना में आज और बेहतर गुणवत्ता। हम जो कुछ भी बनाते हैं, उसकी गुणवत्ता में सुधार करने का संकल्प लें।" भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भारत को एक विकसित देश बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के पूरी तरह अनुरूप है। यह भारत को वैश्विक मंच पर एक गतिशील, विश्वसनीय और दूरदर्शी भागीदार के रूप में स्थापित करता है, जो दोनों क्षेत्रों के लिए समावेशी, मजबूत और भविष्य के लिए तैयार विकास की नींव रखता है। मोदी सरकार ने सिर्फ़ विकसित देशों के साथ ही व्यापार समझौते किए हैं, जो कपड़ा, जूते, रत्न और आभूषण, और हस्तशिल्प जैसे भारत के प्रमुख रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। यह यूपीए शासन से बिल्कुल उल्टा है उन्होंने प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के साथ समझौतों में जल्दबाजी की और अक्सर भारत को मिलने वाले लाभ की तुलना में कहीं अधिक रियायतें दीं।

इसके अलावा, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यूपीए सरकार ने व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने से पहले हितधारकों के साथ कोई सार्थक बातचीत की थी। इसके विपरीत, मोदी सरकार ने अर्थशास्त्रियों, औद्योगिक निकायों, विशेषज्ञों और कई सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद ही मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। परिणामस्वरूप, मोदी सरकार द्वारा हस्ताक्षरित प्रत्येक व्यापार समझौते को उद्योगों से व्यापक सराहना मिली है। मोदी सरकार द्वारा संपन्न प्रत्येक मुक्त व्यापार समझौते ने दोनों पक्षों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं और भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए वैश्विक अवसरों का विस्तार किया है। इन समझौतों ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनने की दिशा में उसकी यात्रा को तेज़ किया है।

यूपीए के कार्यकाल के दौरान, यूरोपीय संघ सहित विकसित देशों की भारत में रुचि कम हो गई थी, क्योंकि आर्थिक विकास धीमा हो गया था, मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी हुई थी और व्यापार का माहौल निराशाजनक था। तब भारत ने ऐसे लाभप्रद व्यापार समझौतों के मूल्यवान अवसर गंवा दिए, जो विकास को गति दे सकते थे और रोजगार पैदा कर सकते थे।

मोदी सरकार द्वारा संपन्न अन्य व्यापार समझौतों के साथ, भारत-ईयू एफटीए, ढुलमुल और निर्णायक नेतृत्व के बीच के अंतर को रेखांकित करता है। जहाँ पहले की सरकारें हिचकिचाती थीं और घुटने टेकती थीं वहीं मोदी सरकार ने बदलाव लाने वाला एक ऐसा समझौता किया है जो बाजारों का विस्तार करने के साथ साथ रोजगार पैदा करता है और भारत के मुख्य हितों की रक्षा करता है। यह इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे मजबूत नेतृत्व और रणनीतिक स्पष्टता नए अवसरों के दरवाजे खोल सकती है, जो देश को समृद्धि के रास्ते पर ले जा सकते हैं।

मिट्टी की मर्यादा और जल की तपस्या से सजेगा 'हरित भविष्य'

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

भारतीय कृषि की गाथा आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। दशकों पहले हमने खाद्यान्न की कमी वाले देश से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों और निर्यातकों की कतार में अपनी जगह बनाई। यह हमारी मेहनत और बेहतर बीजों, सिंचाई के विस्तार व रासायनिक उर्वरकों का ही परिणाम था। लेकिन आज जब मैं अपने गांव जखनी, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश की मिट्टी को छूता हूं, तो विशेषज्ञ एक गंभीर चेतावनी देते सुनाई देते हैं। वे कहते हैं कि जिस रासायनिक बैसाखी के दम पर हमने तरक्की की, उसने हमारी मिट्टी और पाताल के पानी को गहरा जख्म दिया है।

उमाशंकर पांडेय
(पद्मश्री से सम्मानित, जलयोद्धा)

'साइलेंट वेल्थ' पर अदृश्य संकट : मिट्टी सिर्फ धूल नहीं, बल्कि देश की 'साइलेंट वेल्थ' (मौन संपदा है, जो हमारी पूरी खाद्यन्न व्यवस्था की नींव है। लेकिन यूरिया जैसे नाइट्रोजन उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग ने इस संपदा को खोखला कर दिया है। आज हमारी मिट्टी में सिर्फ मुख्य पोषक तत्वों की ही नहीं, बल्कि सल्फर, जिंक और बोरॉन जैसे सूक्ष्म तत्वों की भी भारी कमी हो गई है। नतीजा हमारे सामने है—मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घट रही है और खेतों की पैदावार थम सी गई है।

हमें अब '4R' के मंत्र को जीवन में उतारना होगा : सही स्रोत (Right Source), सही खुराक (Right Dose), सही समय (Right Time) और सही स्थान (Right Place)। यह केवल तकनीक नहीं, बल्कि मिट्टी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है ताकि पोषक तत्वों की बर्बादी न हो और पर्यावरण सुरक्षित रहे ।

जखनी का अनुभव: हर खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ – मेरी जीवन यात्रा सूखे से जूझते बुंदेलखंड के जखनी गांव से शुरू हुई । साल 2005 में जब कोई सरकारी सहायता नहीं थी। बारिश के साथ बहती मिट्टी को खेत में रोकने के लिए कोई योजना भी नहीं थी। तब हमने सामुदायिक एकजुटता से परंपरागत जल संरक्षण "खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़" का अभियान शुरू किया। हमारा लक्ष्य सीधा था—बारिश की हर बूंद को खेत में रोकना और धरती की कोख(एक्वीफर)को फिर से भरना।

आज गर्व होता है कि नीति आयोग ने इस 'जखनी मॉडल' को सराहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेड़बंदी सहित परंपरागत तरीके से जल संरक्षण के लिए देशभर के सरपंचों को पत्र लिखा। जिस बुंदेलखंड के बांदा, चित्रकूट जैसे जिलों में कभी गर्मियों में रेलगाड़ी से पानी आता था, वहां मेड़बंदी के कारण भू-जल स्तर में 1.34 मीटर तक का सुधार देखा गया है। लेकिन एक डर हमेशा बना रहता है—यदि हम जल तो बचा लें, पर उर्वरकों और रसायनों के जहर से मिट्टी को न बचा पाए, तो यह सारी मेहनत बेकार जाएगी। जल संरक्षण के साथ जैविक और प्राकृतिक खेती का संगम ही किसानों के लिए 'सोने पर सुहागा' साबित होगा।

एकीकृत पोषण : परंपरा और तकनीक का मेल – भविष्य की कृषि का आधार एकीकृत पोषण प्रबंधन (INM) है। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि हम उर्वरकों को पूरी तरह त्याग दें, बल्कि उन्हें जैविक खाद, बायो-फर्टिलाइजर और सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ संतुलित करें। सरकार भी इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। फर्मेंटेड जैविक खाद (FOM) और मोलासेस से निकलने वाले पोटाश (PDM) को अब उर्वरक सब्सिडी के दायरे में लाया गया है, ताकि मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन लेवल सुधारा जा सके।

तकनीक भी अब किसान के दरवाजे पर है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) अब महज एक कागज नहीं, बल्कि किसान का गाइड बन रहा है। इसे 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) से जोड़ने की योजना है, जिससे हर खेत को उसकी जरूरत के हिसाब से 'पर्सनलाइज्ड' सलाह मिल सकेगी। गांवों में बन रहे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSKs) अब खेती के 'वन-स्टॉप हब' बन रहे हैं, जहां खाद से लेकर विशेषज्ञ सलाह तक सब एक छत के नीचे उपलब्ध है।

नैनो क्रांति और नीतिगत सुधार – भारत आज नैनो फर्टिलाइजर के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। नैनो यूरिया और लिक्विड बायो-फर्टिलाइजर जैसे उत्पाद न केवल बर्बादी रोकते हैं, बल्कि पैदावार भी बढ़ाते हैं। 'पीएम-प्रणाम' (PM-PRANAM) जैसी योजनाएं राज्यों को रासायनिक खादों का मोह छोड़ने और वैकल्पिक पोषक तत्वों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। साथ ही, कृषि में ड्रोन का प्रवेश 'प्रिसिजन फार्मिंग' यानी सटीक खेती के सपने को सच कर रहा है।

हालांकि, चुनौतियां अभी शेष हैं। यूरिया पर अत्यधिक सब्सिडी के कारण संतुलन अभी भी बिगड़ा हुआ है। हमें ऑर्गेनो-मिनरल फर्टिलाइजर (OMFs) के लिए एक स्पष्ट नियामक ढांचा चाहिए, ताकि खनिज और जैविक तत्वों का दोहरा लाभ खेतों तक पहुंच सके।

एक लचीला भविष्य – जैसे-जैसे भारत विकास के पथ पर अग्रसर होगा, सरकार, उद्योग व खेती करने वाले लोगों के बीच तालमेल बहुत जरूरी होगा। 4R के सिद्धांत को रसायनिक खादों के लिए अपनाने, खेती में आधुनिक तकनीक के विस्तार से बदलाव लाए जा सकते आज मिट्टी की सेहत को प्राथमिकता देकर, भारत का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 2026 की देहरी पर खड़े होकर जब हम विकसित भारत का सपना देखते हैं, तो उसका रास्ता हमारे खेतों की मेड़ों से होकर ही जाता है।

सस्ती तकनीक और हर नागरिक तक पहुंच : AI में आत्मनिर्भर भारत की तैयारी

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आज की सबसे ताकतवर और तेजी से बदलने वाली तकनीक में से एक बनती जा रही है। इसमें यह क्षमता है कि यह देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे, उत्पादन बढ़ाए और विकास की रफ्तार तेज करे। सरकारी सेवाओं को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने में भी एआई अहम भूमिका निभा सकती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीमारी की शुरुआती पहचान, खेती में सही समय पर सही फैसले लेने, आपदा से पहले चेतावनी देने, मौसम और जलवायु का बेहतर अनुमान लगाने और सरकारी योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने में एआई पहले से ही मदद कर रही है। आने वाले समय में शिक्षा, परिवहन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने की संभावना है।

लेकिन जैसे पहले की तकनीकी क्रांतियों में हुआ, वैसे ही एआई के साथ भी असमानता की तस्वीर सामने आती है। जिनके पास कंप्यूटर की ताकत यानी कंप्यूट, अच्छा डेटा और मजबूत डिजिटल ढांचा है, वही बड़े स्तर पर एआई का लाभ उठा पा रहे हैं। जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं, वे पीछे रह जाते हैं। यह फर्क आज केवल कंपनियों के बीच ही नहीं, बल्कि देशों और इलाकों के बीच भी साफ दिखाई देता है।

भारत ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया है। इंडिया एआई मिशन के जरिए भारत यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि एआई की ताकत कुछ गिने-चुने लोगों तक सीमित न रहे। कंप्यूट, डेटा और एआई मॉडल को डिजिटल सार्वजनिक सुविधा के रूप में देखा जा रहा है, ताकि स्टार्टअप, शोधकर्ता, छात्र और छोटे संस्थान भी एआई पर काम कर सकें। भारत की सोच साफ है- ऐसा डिजिटल ढांचा बनाया जाए जो खुला हो, आसानी से बढ़ सके और समाज के हर वर्ग के काम आए। इससे एआई का लाभ आम लोगों तक पहुंचे, देश में ही नवाचार को बढ़ावा मिले और तकनीक के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन सके।

इस सोच के पीछे एक ठोस योजना है। दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत एआई को पांच स्तरों पर विकसित कर रहा है- बिजली और ऊर्जा, कंप्यूट और इंफ्रास्ट्रक्चर, चिप और हार्डवेयर, एआई मॉडल और एप्लिकेशन। इन सभी पर एक साथ काम होने से ही एआई का सही और व्यापक उपयोग संभव हो पाएगा।

सुशील पाल
(संयुक्त सचिव , इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय)

भारत का तरीका इसलिए अलग है क्योंकि यहां एआई तक पहुंच आसान बनाई गई है। भारत ने एक साझा कंप्यूट प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहां 38,000 जीपीयू एक ही पोर्टल पर मिलते हैं। इनका खर्च करीब 65 रुपये प्रति घंटा है, जबकि दूसरे देशों में इसके लिए 2.5 से 3 डॉलर प्रति घंटा तक देने पड़ते हैं। इंडिया एआई मिशन के तहत सरकार एआई मॉडल बनाने के लिए पूरी लागत (100%) तक मदद दे रही है और एआई के इस्तेमाल पर भी 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इससे पैसे की कमी एआई पर काम करने में रुकावट नहीं बनती। इसी वजह से सरवम एआई, सोकेट एआई और ज्ञानि एआई जैसे भारतीय स्टार्टअप अब बिना बड़ी पूंजी लगाए अपने खुद के एआई और भाषा मॉडल बना पा रहे हैं, जो पहले सिर्फ बड़ी विदेशी कंपनियां ही कर पाती थीं।

भारत का लक्ष्य सिर्फ एआई का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि अपना एआई बनाना है। भारत अपना खुद का एआई मॉडल तैयार कर रहा है, जो भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति और भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इसे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट (16-20 फरवरी 2026) में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह मॉडल भारत के ही डेटा पर प्रशिक्षित होगा और देश के भीतर ही काम करेगा।

इससे एआई ज्यादा सटीक, निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाला बनेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि डेटा सुरक्षित रहे और एआई का इस्तेमाल देश के कानूनों और नागरिकों के अधिकारों के अनुसार हो।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में एआई को लेकर केवल जोखिमों की चर्चा नहीं होगी, बल्कि यह देखा जाएगा कि एआई जमीन पर क्या बदलाव ला रही है। इसमें एआई को सबके लिए उपलब्ध कराने, विकास में इसके उपयोग, पर्यावरण की रक्षा, भरोसेमंद सिस्टम, भारतीय भाषाओं में एआई, ग्लोबल साउथ की भागीदारी और एआई से जुड़ी असमानताओं को कम करने जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

भारत का यह तरीका उन देशों के लिए भी एक उदाहरण है, जो अभी विकास के रास्ते पर हैं। यह दिखाता है कि खुलेपन और नवाचार के साथ-साथ अपनी तकनीकी स्वतंत्रता कैसे बनाए रखी जा सकती है। भारत अपने एआई मॉडल ओपन-सोर्स के रूप में विकसित कर रहा है, ताकि दूसरे देश भी अपनी जरूरतों के अनुसार इन्हें अपना सकें। मकसद है मिलकर आगे बढ़ना, बिना किसी नई निर्भरता के।

आज जब एआई देश की ताकत और अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुकी है, सवाल यह नहीं रह गया है कि एआई अपनाया जाए या नहीं, बल्कि यह है कि इसे समझदारी, जिम्मेदारी और टिकाऊ तरीके से कैसे अपनाया जाए।

बजट 2026-27 : पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में रेलवे विकास को नई गति

• **जालंधर ब्रीज** . चंडीगढ़/अंबाला

केंद्रीय रेलवे, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की उपस्थिति में आज एक वर्चुअल बैठक के माध्यम से रेलवे बजट 2026-27 के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए किए गए राज्यवार आवंटन और प्रमुख परियोजनाओं की जानकारी साझा की। बैठक में इन राज्यों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किए जा रहे अभूतपूर्व निवेश पर विशेष जोर दिया गया।

रेल मंत्री ने बताया कि केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेल के लिए रिकॉर्ड 2.93 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक आवंटन का मुख्य फोकस उच्च-गति कनेक्टिविटी, माल ढुलाई क्षमता के विस्तार और यात्रियों की सुरक्षा पर है। वैष्णव ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में पंजाब को रेलवे बजट में रिकॉर्ड 5,673 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान औसत आवंटन की तुलना में लगभग 25 गुना अधिक है। उन्होंने बताया कि राज्य में रेलवे से जुड़े 26,382 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति पर हैं। अमृत स्टेशन योजना के तहत 30 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण/पुनर्विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही पंजाब ने 100 प्रतिशत रेलवे विद्युतीकरण हासिल कर लिया है, जिससे परिचालन दक्षता, कनेक्टिविटी और पर्यावरणीय स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। रेल मंत्री ने बताया कि हरियाणा को रेलवे बजट में रिकॉर्ड 3,566 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। राज्य में 12,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में रेलवे का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा हो चुका है तथा 34 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है।

वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत से राज्य में यात्रियों की सुविधा और कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार हुआ है। एक प्रश्न के उत्तर में वैष्णव ने बताया कि हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन की टेस्टिंग और संबंधित कार्य जारी है और उन्होंने आशा व्यक्त की कि शीघ्र ही हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन का उद्घाटन हरियाणा में किया जाएगा। चंडीगढ़ के संबंध में रेल मंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य तेजी से चल रहा है।

अब तक लगभग दो वर्षों का कार्य पूरा हो चुका है और शेष तीन वर्षों में कार्य पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि चंडीगढ़ में पूरी तरह एक नया और आधुनिक रेलवे स्टेशन निर्मित किया जा रहा है। वैष्णव ने बताया कि हिमाचल प्रदेश को 2,911 करोड़ रुपए का रेलवे बजट आवंटन दिया गया है और राज्य में 17,700 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, हालांकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कुछ प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने के कारण कुछ परियोजनाओं में देरी हुई है।

रेल मंत्री ने हिमाचल प्रदेश सरकार से रेलवे परियोजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सहयोग की अपील की। रेल मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि जम्मू-कश्मीर के लिए 1,086 करोड़ रुपए का रेलवे बजट आवंटन किया गया है, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और विकास को और बल मिलेगा। बैठक के अंत में वैष्णव ने दोहराया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य भारतीय रेलवे को तेज, सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन प्रणाली के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड बजट आवंटन और नई परियोजनाओं के माध्यम से रेलवे राष्ट्रीय विकास और 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। अंबाला स्थित उत्तर रेलवे मंडल प्रबंधक के कार्यालय में आयोजित वर्चुअली कांफ्रेंस में जुड़े पत्रकारों के साथ अंबाला मंडल रेल प्रबंधक विनोद भाटिया और नवीन कुमार झा, सीनियर डीसीएम भी उपस्थित रहे।

संत रविदास जयंती के पावन अवसर पर श्री गुरु रविदास महाराज जी के शाश्वत आदर्शों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि

ये हमारे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है कि संत रविदास जयंती के पावन अवसर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट को 'श्री गुरु रविदास महाराज जी' एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। ये हम सबके लिए अत्यंत खुशी का दिन है। ये श्री गुरु रविदास महाराज जी के शाश्वत आदर्शों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि है। समानता, करुणा और सेवा का उनका संदेश हम सभी को गहराई से प्रेरित करता है।

हलवारा एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन लुधियाना को नई उड़ान

हलवारा हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का उद्घाटन पंजाब के लोगों, विशेषकर लुधियाना और आसपास के क्षेत्रों के लिए अत्यंत खुशी का अवसर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लुधियाना उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। यह शहर अपने उद्यमी लोगों के लिए जाना जाता है। हमारी सरकार इस शहर की हवाई संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जो आधुनिक हवाई अड्डे के लिए चल रहे कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

जी राम जी अधिनियम और लचीली एवं सतत् आजीविकाओं की दिशा में भारत की यात्रा

• **जालंधर ब्रीज** . चंडीगढ़/अंबाला

पिछले लगभग दो दशकों से ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम भारत की सामाजिक सुरक्षा संरचना का केंद्रीय स्तंभ रहे हैं। वर्ष 2005 में अधिनियमित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) ने ग्रामीण परिवारों को आय सुरक्षा प्रदान की है, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार किया है तथा आवश्यक सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन में योगदान दिया है। जैसे-जैसे ग्रामीण भारत तीव्र आर्थिक, प्रौद्योगिक और पर्यावरणीय परिवर्तनों से गुजर रहा है, उभरती चुनौतियों और अवसरों का प्रभावी ढंग से उत्तर देने के लिए इस ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने की तात्कालिक आवश्यकता है।

डॉ. विभा धवन
(महानिदेशक, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी))

विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 इस क्रमिक विकास को प्रतिबिंबित करता है। ग्रामीण रोजगार गारंटी ढांचे में सुधार के माध्यम से यह अधिनियम इस तथ्य को मान्यता देता है कि सतत् ग्रामीण समृद्धि केवल रोजगार सृजन पर ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जलवायु जोखिमों के प्रति लचीलेपन तथा आजीविकाओं के संरक्षण पर भी आधारित होनी चाहिए। यह समेकित दृष्टिकोण ऐसे समय में अत्यंत प्रासंगिक है, जब ग्रामीण समुदाय जलवायु परिवर्तनशीलता, चरम मौसमीय घटनाओं और संसाधन दबाव के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता का सामना कर रहे हैं।

जी राम जी अधिनियम क्यों विशिष्ट है : जी राम जी अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें मजदूरी आधारित रोजगार को चार प्राथमिक क्षेत्रों के साथ संरेखित करने पर विशेष बल दिया गया है—जल सुरक्षा, मूल ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से संबंधित अवसंरचना तथा चरम मौसमीय घटनाओं के शमन से जुड़े कार्य। यह ग्रामीण रोजगार नीति के पर्यावरणीय और लचीलापन संबंधी आयामों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जल से संबंधित कार्य, मृदा एवं भूमि संरक्षण, जल निकासी प्रणालियाँ तथा जलवायु-अनुकूल अवसंरचना कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के साथ-साथ बाढ़, सूखा और भूमि क्षरण के प्रति संवेदनशीलता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब ऐसी परिसंपत्तियां प्रभावी ढंग से नियोजित तथा कार्यान्वित की जाती हैं, तो वे कई लाभ उत्पन्न करती हैं—अल्पकालिक रोजगार सृजन, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन तथा दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा। इन क्षेत्रों पर अधिनियम का विशेष बल इस तथ्य को रेखांकित करता है कि रोजगार कार्यक्रम एक साथ सामाजिक संरक्षण और जलवायु अनुकूलन के प्रभावी साधन के रूप में कार्य कर सकते हैं।

स्थानीय स्तर पर लचीलापन : अधिनियम की नियोजन पारिस्थितिकी—जिसका केंद्र विकसित ग्राम पंचायत योजनाएँ हैं तथा जिसमें परिसंपत्तियों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के अंतर्गत एकीकृत किया गया है—ग्रामीण विकास के लिए एक सुसंगत और भविष्य के लिए तैयार दृष्टिकोण को समर्थन प्रदान करती है। विकेन्द्रीकृत नियोजन के माध्यम से पंचायतों को स्थानीय प्राथमिकताओं की पहचान करने का अवसर मिलता है, जबकि राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण व्यापक अवसंरचना एवं विकास उद्देश्यों के साथ समन्वय सुनिश्चित करता है। कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से यह ढांचा रोजगार गारंटी के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, स्थायित्व और प्रासंगिकता में सुधार का अवसर प्रदान करता है। पर्याप्त तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से पंचायती राज संस्थान यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि सार्वजनिक कार्य, संसाधन संरक्षण तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सार्थक योगदान दें।

आयकर विभाग द्वारा नए आयकर अधिनियम और टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों पर सेमिनार का आयोजन

हितधारकों की क्षमता निर्माण हमारा प्रमुख उद्देश्य : संयुक्त आयकर आयुक्त

• **जालंधर ब्रीज.** अमृतसर

आयकर विभाग, टीडीएस चार्ज, अमृतसर ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय (जीएनडीयू), अमृतसर में नए आयकर अधिनियम, नए टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों और उनके अनुपालन पर एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार को लुधियाना के संयुक्त आयकर आयुक्त भूपिंदर सिंह और अमृतसर के आयकर अधिकारी विकास कुमार ने संबोधित किया। वक्ताओं ने प्रतिभागियों को नए आयकर अधिनियम, 2025 की प्रमुख विशेषताओं, हालिया संशोधनों, नए टीडीएस/टीसीएस अनुभागों, प्रक्रियात्मक पहलुओं और वैधानिक अनुपालन आवश्यकताओं से अवगत कराया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य डीडीओ के तौर पर सेवा निभा रहे अधिकारियों और अन्य हितधारकों में जागरूकता बढ़ाना, प्रक्रियात्मक विसंगतियों को कम करना तथा कर कटौती और संग्रहण में समयबद्ध एवं सटीक अनुपालन को प्रोत्साहित करना था। टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के अंतर्गत गैर-अनुपालन एवं चूक के परिणामों पर भी प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को अधिकारियों से सीधे संवाद करने और अपने सवालों का जवाब जानने का मौका मिला। सभा को संबोधित करते हुए श्री भूपिंदर सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य टीडीएस एवं टीसीएस के अंतर्गत नए कर प्रावधानों पर व्यापक जानकारी प्रदान कर हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना है, जो कि सीबीडीटी की 'हितधारकों की क्षमता निर्माण' पहल के अनुरूप है।

यह सेमिनार शैक्षणिक संस्थानों के साथ संवाद स्थापित करने और सूचित कर व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए आयकर विभाग के सतत प्रयासों का हिस्सा थी। विभाग ने देशभर में कर नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कराधान और अनुपालन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

जालंधर में 'साढ़े बुजुर्ग साढां मान' अभियान की शुरुआत 16 से

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

बुज़ुर्गों की भलाई के लिए प्रशासन द्वारा 16 फरवरी, 2026 से ज़िले में 'साढ़े बुजुर्ग साढां मान' कैंपेन शुरू किया जा रहा है। इस बारे में एक मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) अमनिंदर कौर ने कहा कि अभियान के तहत 16 मार्च, 2026 तक बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य, योग और मनोवैज्ञानिक सहायता पर देखभाल के लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बुज़ुर्गों को अधिक आयु में होने वाली परेशानियों जिनमें मोतियाबिंद, जोड़ों का दर्द और दूसरी शारीरिक बीमारियों के इलावा उनके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए स्पेशल चेक-अप कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इन कैंपों का समय पर प्रबंध करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि बुज़ुर्गों की स्वास्थ्य संभाल के लिए योग कैंप भी लगाए जाएंगे। बुज़ुर्गों और युवाओं में संपर्क बढ़ाने के लिए सांस्कृति गतिविधियां भी करवाई जाएंगी। इसके अलावा, बुज़ुर्गों को सरकारी स्कीमों की जानकारी देने के लिए जागरूकता प्रोग्राम भी करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बुज़ुर्ग हमारे समाज का अहम हिस्सा हैं और उनका सम्मान, सुरक्षा और देखभाल करना केवल सरकार की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की सांझा ज़िम्मेदारी है।

अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने सभी विभाग को बुज़ुर्गों की भलाई के लिए इस कैंपेन को सफलता चलाने के लिए आपस में तालमेल से काम करने के निर्देश दिए। मीटिंग में समाजिक सुरक्षा अधिकारी नरेश कुमार, सचिव जिला क्रॉस सोसाइटी सुरजीत लाल के अलावा स्वास्थ्य, यूथ युवक सेवाएं, शिक्षा विभाग समेत अलग-अलग विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

तकनीकी शिक्षा में अनाथ और नेत्रहीन युवाओं के लिए वित्तीय बाधाओं को किया दूर

मान सरकार ने 'कोपा' ट्रेड में अनाथ और नेत्रहीन विद्यार्थियों की आईटीआई फीस की माफ : हरपाल सिंह चीमा

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा जन-हितैषी निर्णय लेते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा-वीआई) ट्रेड में दाखिला लेने वाले अनाथ एवं नेत्रहीन विद्यार्थियों की प्रशिक्षण फीस माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में फाइल को मंजूरी दिए जाने के बाद इस निर्णय की पुष्टि करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह कदम भगवंत मान सरकार की उस दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि आर्थिक तंगी कभी भी जरूरतमंद विद्यार्थियों की व्यावसायिक प्रगति में बाधा नहीं बननी चाहिए। वित्त मंत्री ने बताया कि अनाथ आश्रमों और नेत्रहीन बच्चों के लिए स्थापित स्कूलों से आने वाले विद्यार्थी अब 'कोपा-वी.आई.' ट्रेड के लिए 100 फीसदी फीस माफी के पात्र होंगे। यह लाभ वर्तमान समय में यह कोर्स चला रहे 9 सरकारी संस्थानों में लागू किया जाएगा।

वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि हालांकि फीस माफी से राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सरकार इसे वित्तीय बोझ के बजाय मानव पूंजी में एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देखती है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर 29 जनवरी 2026 को हुई बजट बैठकों के दौरान विस्तार से चर्चा की गई थी, जहां संबंधित प्रशासनिक विभाग की सिफारिशों की जांच-पड़ताल के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मंजूरी दी गई।

सामाजिक सुरक्षा संहिता नियम, 2020 पर संगोष्ठी का आयोजन

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़/मोहाली

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), चंडीगढ़ द्वारा श्रम विभाग, पंजाब सरकार के सहयोग से पंजाब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान (ईईसी -2025), प्रधानमंत्री-विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) एवं सामाजिक सुरक्षा संहिता (सीओएसएस) नियम, 2020 पर एक संगोष्ठी का आयोजन श्रम भवन, मोहाली में किया गया। संगोष्ठी में पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

भारत सरकार के श्रम सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कर्मचारी नामांकन अभियान (ईईसी -2025) के व्यापक प्रसार हेतु राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके विभागों द्वारा नियोजित ठेकेदारों एवं संविदा कर्मियों को इस अभियान की समुचित जानकारी दी जाए। इस पहल का उद्देश्य पात्र आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। ईपीएफओ की ओर से इस कार्यक्रम में रितेश सैनी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I, जोनल कार्यालय, चंडीगढ़ तथा दीपक पाल, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। श्रम विभाग, पंजाब सरकार की तरफ से बलजीत सिंह, उप श्रम आयुक्त, अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ उपस्थित रहे। संगोष्ठी में पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करते हुए कुल 62 अधिकारियों ने भाग लिया।

संगोष्ठी के दौरान दीपक पाल, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II ने कर्मचारी नामांकन अभियान (ईईसी -2025) पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि यह अभियान पहले से अपंजीकृत पात्र कर्मचारियों, विशेषकर आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों को, सुविधा-आधारित एवं स्वैच्छिक अनुपालन दृष्टिकोण के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। अभियान के अंतर्गत क्षतिपूर्ति में छूट एवं नामांकन प्रक्रिया के सरलीकरण जैसे लाभों की भी जानकारी दी गई।

प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री-विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) की प्रमुख विशेषताओं से भी अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त, सामाजिक सुरक्षा संहिता (सीओएसएस) नियम, 2020 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई, जिसमें नियोक्ताओं की वैधानिक जिम्मेदारियों तथा ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

संगोष्ठी का समापन एक संवादात्मक सत्र के साथ हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने संविदा कर्मियों के कवरेज, अनुपालन आवश्यकताओं तथा सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित व्यावहारिक एवं प्रकरण-आधारित प्रश्नों पर चर्चा की। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।

पीएपी की क्रिकेट टीम ने जीता पहला इंटर रेंज पंजाब पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

पंजाब सरकार के नशा विरोधी अभियान 'युद्ध नशे के विरुद्ध' और 'गैंगस्टर्स पर वार' के अभियानों में मसरूफ पंजाब पुलिस के मानसिक मनोबल को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल पुलिस, स्टेट आर्म्ड पुलिस, जालंधर एम.एफ. फारूकी के प्रयासों से पहला इंटर रेंज पंजाब पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट पी.ए.पी. ग्राउंड, जालंधर में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 17 टीमों ने भाग लिया। इन टीमों के 4 ग्रुप बनाकर लीग मैच, क्वार्टर फाइनल, सेमी फाइनल और फाइनल मैच करवाए गए। टूर्नामेंट के मुकाबलों में जीत अनुसार दफ्तर सेंट्रल स्पोर्ट्स, पंजाब पुलिस और पी.ए.पी. क्रिकेट टीमों ने फाइनल में प्रवेश किया।

डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, प्रशासन, पी.ए.पी. इंदरबीर सिंह के नेतृत्व में फाइनल मैच करवाया गया। रोमांचक फाइनल मैच में दोनों टीमों द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। पी.ए.पी. की क्रिकेट टीम ने जीत हासिल करते हुए पहला इंटर रेंज पंजाब पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम की। इस मौके सभी टीमों के नोडल अधिकारियों को सम्मानित किया गया।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रमणीक सिंह रंधावा ने मॉडल टाउन श्मशान घाट का किया दौरा

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर के चेयरमैन रमणीक सिंह रंधावा ने आज मॉडल टाउन में मौजूद श्मशान घाट का दौरा किया और वहां प्रस्तावित सुधार और विकास कार्यों की गुंजाइश का रिव्यू किया। चेयरमैन रमणीक सिंह रंधावा ने श्मशान घाट की मौजूदा हालत का जायजा लिया और आने वाली सुधार योजना पर डिटेल में चर्चा की। योजना में श्मशान घाट के सौन्दर्यीकरण, उचित विकास, बेहतर सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटेशन मैनेजमेंट और जनता की सुविधा के लिए सही पार्किंग बनाने जैसे ज़रूरी प्वाइंट शामिल है।

इस मौके पर सोसायटी ने राज्यसभा मेंबर अशोक कुमार मित्तल का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने श्मशान घाट के सुधार और विकास के लिए 1 करोड़ रुपये की ग्रांट को मंज़ूरी दी। यह ग्रांट नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए सरकार की वचनबद्धता को दर्शाती है। इस मौके पर रंधावा के साथ वरिंदर मलिक, जसविंदर सिंह साहनी, कंवलजीत सिंह (टोनी), राजीव दुग्गल, ललित त्रिखा और स्वतंत्र चावला भी मौजूद थे।

एससी कमीशन द्वारा जातिसूचक शब्द प्रयोग करने संबंधी एसएसपी अमृतसर से रिपोर्ट तलब

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने एक मामले में स्वतः संज्ञान (सू मोटो नोटिस) लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.) अमृतसर से रिपोर्ट मांगी है। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि अमृतसर में अनुसूचित जातियों से संबंधित विभिन्न संगठनों द्वारा एक व्यक्ति को नौकरी से निकाले जाने के विरोध में धरना लगाया गया था। उस धरने के दौरान एक पुलिस अधिकारी द्वारा धरना देने वालों के खिलाफ जातिसूचक शब्दों के प्रयोग करने का मामला सोशल मीडिया तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से उनके ध्यान में आया है। उन्होंने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस संबंधी 10 फरवरी, 2026 को एसपी हरपाल सिंह को इस मामले संबंधी रिपोर्ट सहित तलब किया गया है।

बीबीएमबी तलवाड़ा द्वारा अंडर वाटर सर्वे पर एक दिवसीय ऑनलाइन तकनीकी कार्यशाला का आयोजन

• **जालंधर ब्रीज.** तलवाड़ा

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड तलवाड़ा में अंडर वाटर सर्वे से संबंधित आधुनिक तकनीकों के बारे में अधिकारियों एवं इंजीनियरों को अद्यतन करने के उद्देश्य से एक दिवसीय ऑनलाइन तकनीकी कार्यशाला का आयोजन मुख्य अभियंता राकेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर उप मुख्य अभियंता वी.के. मीना, अधीक्षण अभियंता मनवीन चौधरी, अधिशाषी अभियंता विनय कुमार, हरप्रीत सिंह तथा गौरव लाम्बा के अतिरिक्त विभिन्न इकाइयों से एसडीओ एवं जूनियर इंजीनियरों ने भी कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला के दौरान अंडर वाटर सर्वे में प्रयुक्त नवीनतम तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल , अंडर वाटर कैमरा सिस्टम, सोनार तकनीक, बाथीमेट्रिक सर्वे, सुरंगों, बांधों तथा हाइड्रो-मैकेनिकल संरचनाओं की जांच से संबंधित तकनीकी विधियों को स्पष्ट रूप से समझाया गया। मुख्य अभियंता राकेश कुमार गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि अंडर वाटर सर्वे तकनीकें बांधों, नदियों, सुरंगों एवं अन्य जल संरचनाओं की सुरक्षा तथा दीर्घकालिक टिकाऊ कार्यक्षमता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

बलजिंदर सिंह बंटी ने पंजाब राज्य वन विकास निगम के वाइस चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला

वन मंत्री लाल चंद कटारूचक और रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत की उपस्थिति में संभाला पद

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

बलजिंदर सिंह बंटी ने सेक्टर-68, मोहाली स्थित वन परिसर में पंजाब राज्य वन विकास निगम (पी.एस.एफ.डी.सी.) के नए वाइस चेयरमैन के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने वन एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक, रक्षा सेवाएं कल्याण, स्वतंत्रता सेनानी एवं बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में यह पद संभाला। इस अवसर पर वन मंत्री लाल चंद कटारूचक ने बलजिंदर सिंह बंटी को यह प्रतिष्ठित जिम्मेदारी सौंपने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नए वाइस चेयरमैन वन विभाग के विकास-केंद्रित एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे, जो पौधरोपण और हरियाली बढ़ाने पर केंद्रित है।

नवनियुक्त वाइस चेयरमैन को बधाई देते हुए कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि इस नियुक्ति के द्वारा जमीन से जुड़े एक समर्पित कार्यकर्ता को सम्मान दिया गया है।

राष्ट्रीय संयोजक 'आप' अरविंद केजरीवाल, पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक द्वारा उन पर विश्वास जताने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए वाइस चेयरमैन बलजिंदर सिंह बंटी ने भरोसा दिलाया कि वे उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा पंजाब गऊ सेवा आयोग के वाइस चेयरमैन कीमती भगत, पंजाब राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष राकेश पुरी, मुख्य वन्यजीव वार्डन बसंता राज कुमार और ए.पी.सी.सी.एफ. एवं सी.ई.ओ. (पनकैंपा) सौरभ गुप्ता भी उपस्थित थे।

टी20 विश्व कप : पाकिस्तान के बायकॉट पर गरजे सूर्या कुमार

बोले- कोलंबो में होने वाले मैच के लिए भारतीय टीम के टिकट पहले ही हो चुके हैं बुक

फोटो-बीसीसीआई

स्पोर्ट्स डेस्क. टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कैप्टन्स डे पर बोलते हुए कहा कि भारत ने आगामी टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार नहीं किया है बल्कि इसका खंडन पाकिस्तान की ओर से आया है। उन्होंने आगे कहा कि कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो में होने वाले इस महत्वपूर्ण मैच के लिए भारतीय टीम के टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं। पाकिस्तान सरकार ने कोलंबो में होने वाले इस महत्वपूर्ण मैच में अपनी क्रिकेट टीम को खेलने की अनुमति नहीं दी है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन इसे बांग्लादेश के प्रति एकजुटता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। टूर्नामेंट से पहले कप्तानों की बैठक में बोलते हुए सूर्यकुमार ने कहा कि भारत तय योजना के अनुसार कोलंबो जाएगा और मैच के लिए तैयार रहेगा, भले ही पाकिस्तान मैदान पर उतरने से इनकार कर दे। उनके अनुसार, इस स्थिति की जिम्मेदारी भारत पर नहीं है। सूर्यकुमार ने कहा कि हमारा नजरिया एकदम स्पष्ट है। हमने उनके साथ खेलने से मना नहीं किया है, उन्होंने ही मना किया है। हमारी उड़ानें बुक हो चुकी हैं और हम कोलंबो जा रहे हैं। हमारा शेड्यूल तैयार है - पहले अमेरिका, फिर कनाडा और उसके बाद हम कोलंबो के लिए रवाना होंगे। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर भारत में अपने मैच खेलने से इनकार करने के बाद बांग्लादेश को विश्व कप से बाहर कर दिया गया था।

टूर्नामेंट शनिवार, 7 फरवरी से शुरू हो रहा है और बीसीसीआई और आईसीसी के साथ हुए समझौते के तहत पाकिस्तान को अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलने हैं। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले ही चेतावनी दे दी है कि इस महत्वपूर्ण मैच का बहिष्कार करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, और कहा है कि ऐसा निर्णय खेल के व्यापक हित में नहीं होगा। यह विवाद बीसीसीआई के निर्देश पर बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद शुरू हुआ, जिसका कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया।

सरकारी स्कूलों ने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए मेडिटेशन को अपनाया : हरजोत बैंस

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि मोहाली जिले के सरकारी अपर-प्राइमरी स्कूलों ने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक बड़ी और नवीन पहल करते हुए 'रोजाना मेडिटेशन प्रोग्राम' की शुरुआत की है। बैंस और आप पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने मोहाली में एक वर्कशॉप के दौरान स्कूल प्रमुखों और प्रिंसिपलों के साथ विचार-विमर्श किया। शिक्षा मंत्री ने छात्रों की तंदरुस्ती बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किए गए 'रोजाना मेडिटेशन प्रोग्राम' के क्रियान्वयन और प्रभावों के बारे में वर्कशॉप में मौजूद लोगों को अवगत करवाया। 'न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (एनआईएलपी)' जैसे शैक्षिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि यह पायलट प्रोजेक्ट 19 जनवरी, 2026 को शुरू किया गया था। इसके तहत रोजाना अभ्यास में सुबह की सभा के बाद 30 मिनट का मेडिटेशन सत्र करवाया जाता है।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at DB Corp Ltd, J7 NEAR BUS STAND SUBHANPUR (HAMIRA), KAPURTHALA, PUNJAB - 144808, and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.